न्यूज इन नंबर्स

महिला साक्षरता में
मुंगेर सबसे आगे सहरसा फिसड्डी

राष्ट्रीय साक्षरता दर

82.14% पुरुष

65.46% महिलाएं

बिहार में साक्षरता दर

73.39% पुरुष

53.33% महिलाएं

जनगणना 2011 के मुताबिक महिला साक्षरता दर में बिहार में एक दशक में सबसे अधिक (20%) की वृद्धि हुई

इसके लिए बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया

अक्षर आंचल योजना के तहत करीब 30 लाख महिलाएं हुईं साक्षर

प्रमुख राज्यों की साक्षरता दर

राज्य	पुरुष	महिला
केरल	96.0	92.00
हिमाचलप्रदेश	90.8	76.6
महाराष्ट्र	89.8	75.5
गुजरात	87.2	70.7
पंजाब	81.5	71.3
यूपी	79.2	59.3
झारखंड	78.5	56.2
बिहार	73.5	53.3

बिहार (एक नजर में)

- सबसे अधिक साक्षरता : रोहतास (75.59)
- सबसे कम साक्षरता : पूर्णिया (52.49)
- सबसे अधिक महिला साक्षरता : मुंगेर (65.53)
- सबसे कम महिला साक्षरता: सहरसा (42.73)
- सबसे अधिक पुरुष साक्षरता : रोहतास (85.24)
- सबसे कम पुरुष साक्षरता : कटिहार (60.99)

सभी आंकड़ें प्रतिशत में

रिपोर्ट : ब्रजेश, प्रस्तुति : मनीष कुमार

मौसम जिलों का

तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

शहर	न्यून.	अधिक.
पटना	26.7	35.6
गया	25.6	34.6
भागलपुर	28.3	35.6
पूर्णिया	26.0	35.0
मुजफ्फरपुर	26.8	35.7

पूर्वानुमान

उत्तर बिहार में कहीं तेज तो कहीं कम बारिश की है संभावना

क्विक न्यूज

■ **मुख्यमंत्री का जनता दरबार कल :**

पटना . सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होगा. इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति-जनजाति व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना एवं प्रावैधिकी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग और सांस्थिक वित्त से संबंधित विभागों से जुड़ी शिकायतें सुनी जायेंगी. मुख्यमंत्री के सचिव अतिश चंद्रा के अनुसार शिकायत पत्रों का निबंधन उसी दिन सुबह साढ़े सात बजे से दिन के 11 बजे तक किया जायेगा. 10 बजे से मुख्यमंत्री फरियादियों की शिकायतों का निबटारा शुरू कर देंगे.

■ **हर पंचायत में आज मनेगा साक्षरता दिवस : पटना.** अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर रविवार को राज्य की हर पंचायत में कार्यक्रम होगा. बैनर-पोस्टर के साथ नवसाक्षर व संबंधित कर्मचारी प्रभात रैली निकालेंगे. शिक्षा विभाग ने जिला व प्रखंड के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोक शिक्षा केंद्रों में कार्यक्रम निश्चित रूप से करें, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाएं. जन शिक्षा के उपनिदेशक संजय कुमार कुंदन ने कहा कि आठ सितंबर को नये साक्षरता केंद्र की स्थापना भी करनी है. इसके तहत स्वयंसेवी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत उन पंचायतों में होगी, जहां पर अभी तक यह कार्य लंबित है.

■ **गुजरात समिट से लाभान्वित होंगे बिहार के किसान : पटना.** गुजरात में होनेवाले वाइब्रेंट ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट में बिहार से गये किसान खेती-किसानी में दक्ष होकर लौटेंगे. बिहार सरकार के तमाम विरोध के बावजूद सम्मिट में भाग लेने गये सूबे के किसान खेती की नयी तकनीक व गुर सीख कर लौटेंगे. भाजपा के मुख्य प्रवक्ता विनोद नारायण झा ने कहा कि मोदी से व्यक्तिगत खुन्नस के कारण किसानों को गुजरात जाने से रोकने का नीतीश सरकार का प्रयास विफल रहा. कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रादेशिक पुरस्कार लेनेवाले राज्य के 42 किसान सम्मिट में भाग ले रहे हैं.

■ **लोस चुनाव को लेकर रालोसपा की बैठक आज : पटना.** लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को छपरा में होगी, जिसमें दूसरे दल से गंठबंधन पर विचार होगा. पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि छपरा के नगरपालिका भवन में बैठक होगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ अरुण कुमार व अन्य नेता बैठक में शामिल होंगे. बाढ़-सुखाड़ पर भी विचार-विमर्श किया जायेगा. रालोसपा का मानना है कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता के प्रति गंभीर नहीं है.

■ **भारतीय जनता मजदूर महासंघ की कमेटी गठित : पटना.** भारतीय जनता मजदूर महासंघ की प्रदेश कमेटी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष चंद्र किशोर चौधरी ने की. सूची के अनुसार, चंद्रकांता सिन्हा महामंत्री, मनोज झा, माधुरी पासवान, महेश शर्मा व उदय कृष्ण यादव उपाध्यक्ष, हरिवंश कुमार, कृष्णदेव सिंह व राजेंद्र मंडल मंत्री, चंद्रशेखर सिंह कोषाध्यक्ष, सुशील कुमार वर्मा प्रवक्ता, अरुण कुमार सिन्हा व मंती दास मीडिया प्रभारी बने हैं. साथ ही निर्माण मजदूर महासंघ, भारतीय जनता ऑटोचालक संघ, भारतीय खेतिहर मजदूर महासंघ आदि की भी नयी कमेटियों का भी गठन कर दिया गया है.

हेल्थ काउंसेलिंग आज

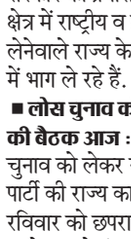

इस बार प्रभात खबर, ऑनलाइन हेल्थ काउंसेलिंग में रविवार को दोपहर एनएमसीएच के चर्म व कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉ एमके सिन्हा मौजूद रहेंगे. पाठक किसी भी तरह के स्कीन व कुष्ठ रोग संबंधी उपचार व बचाव के बारे में जानकारी फोन से मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं.

समय : दोपहर 12 से 1 बजे
फोन नंबर : 0612-3200112, 0612-3058377

अंधेर नीति . राज्य व केंद्र के टकराव से बिगड़ी बात

ट्रांसफॉर्मर जले, नौ हजार गांव अंधेरे में

संवाददाता , पटना

राज्य में नौ हजार ट्रांसफॉर्मर खराब या जले हुए हैं. 16, 25 या 40 केवीए की क्षमतावाले इन ट्रांसफॉर्मरों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य भर में लगाया गया था. केंद्र व राज्य सरकार के बीच जारी जिच के कारण नौ हजार से अधिक गांव अंधेरे में हैं. इन ट्रांसफॉर्मरों से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को बिजली मिलती है.

अपनी-अपनी दलील

योजना के तहत राज्य में 45,459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये हैं. अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 9,046 जल चुके हैं. इन्हें बदलने में केंद्र व राज्य सरकार की अपनी-अपनी दलील है. राज्य सरकार का कहना है कि आखिर एक गांव में कम क्षमता के ट्रांसफॉर्मर देने से यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि बीपीएल परिवार को छोड़ और अन्य लोग उससे बिजली का उपभोग नहीं करेंगे. हर साल होनेवाले ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव इस मामले को उठाते रहे हैं. बिहार सरकार का तर्क रहा है कि गांवों की सामाजिक संरचना ऐसी नहीं है कि केवल गरीबों के घर तक ही बिजली की सुविधा पहुंचा दी जाये. साथ ही अगर गारंटी/वारंटी अवधि में ट्रांसफॉर्मर जलता है, तो उसे बदलने की जिम्मेवारी भी संबंधित एजेंसी की ही है. ट्रांसफॉर्मर लगानेवाली एजेंसियों की अपनी दलील है. इनका कहना है कि अगर मैकेनिकल या ट्रांसफॉर्मर के पुरजों में खराबी आये और जल जाये तो उसे वारंटी/गारंटी अवधि में बदला जा सकता है.

ट्रांसफॉर्मर
45,459
नॉर्थ बिहार
26157
साउथ बिहार
19302
जले
9046

■ इन्हीं ट्रांसफॉर्मरों से गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को मिलती है बिजली

बदलने की कवायद तेज

अब इन जले ट्रांसफॉर्मरों को तेजी से बदलने की कवायद शुरू कर दी गयी है. हाल ही में राज्य सरकार ने सांसद कोष व मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से इन जले ट्रांसफॉर्मर को बदलने या उच्च क्षमता का लगाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा इन जले ट्रांसफॉर्मरों को मरम्मत कर वैसे उपभोक्ताओं को भी दिया जा रहा है, जो निर्धारित राशि का भुगतान कर उसे निजी उपयोग के लिए खरीदना चाहते हैं. अब जिलाधिकारी के माध्यम से भी इन जले ट्रांसफार्मरों को भी बदला जायेगा.

डीएम के माध्यम से बदलेगा

कम क्षमतावाले खराब या जले ट्रांसफॉर्मर या पांच पोल तक निम्न क्षमता का तार बदलने व बिजली आपूर्ति से संबंधित अन्य काम जिलाधिकारी के स्तर पर होगा. जिला प्रशासन के स्तर पर होनेवाले इन कार्यों को 'जिलांतर्गत विशेष विद्युत कार्य' की श्रेणी में रखा जायेगा. ऊर्जा सचिव सह बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संदीप पौंड्रिक की ओर से जारी आदेश के अनुसार ट्रांसफॉर्मर बदलने का प्रस्ताव डीएम के स्तर पर संबंधित इलाके के कार्यपालक अभियंताओं को दिया जायेगा. ट्रांसफॉर्मर या तार बदलने का ठेका जारी होगा. पूरी राशि जारी होने पर ही कार्यपालक अभियंता कार्यादेश जारी करेंगे.

राजद नेताओं को सौंपी गयी जिलों की जवाबदेही

पटना. पार्टी कार्यक्रमों को जिलों में प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर राजद ने जिला प्रभारियों की तैनाती की है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे ने पार्टी नेताओं को जिलों का प्रभार दिया है. **ये बने प्रभारी :** पटना- प्रो गुलाम गौस, पटना महानगर- डॉ प्रेम कुमार गुप्ता, गया- सुरेश पासवान, गया महानगर- डॉ रामानुज प्रसाद, पश्चिम चंपारण-सीताराम सिंह, बगहा- सतीश पासवान, पूर्वी चंपारण- रघुनाथ झा, गोपालगंज- रामविचार राय, सीवान- मुनेश्वर चौधरी, सारण-बसावन प्रसाद भगत, वैशाली- सीताराम यादव, मुजफ्फरपुर- रामलखन राम रमण, मुजफ्फरपुर महानगर- चितरंजन गगन, सीतामढ़ी- रामाशीष यादव, शिवहर- सूर्यदेव राय, मधुबनी- अब्दुल बारी सिद्दीकी, दरभंगा-अली अशरफ फातमी, दरभंगा महानगर- प्रो विजय कुमार जायसवाल, समस्तीपुर-तनवीर हसन, बेगूसराय- प्रो सुधांशु शेखर भास्कर, सुपौल- अशोक कुमार सिंह, सहरसा- प्रो चंद्रशेखर, मधेपुरा - प्रो अब्दुल गफूर, अररिया- प्रो खालिद, किशनगंज- इंद्रानंद यादव,पूर्णिया- प्रो सुरेंद्र प्रसाद सिंह, कटिहार- अख्तरुल ईमान, भागलपुर- मो जावेद इकबाल अंसारी, बांका- नंद किशोर राम, मुंगेर- विजय कृष्ण, खगड़िया- सम्राट चौधरी, लखीसराय- रामबदन राय, शेखपुरा- महेंद्र सिंह, जमुई- राजनीति प्रसाद,नालंदा- आजाद गांधी, भोजपुर- कांति सिंह, बक्सर- सीताराम प्रसाद अकेला, रोहतास- मुंद्रिका सिंह यादव, कैमूर- ललन पासवान आदि.

स्कूलों को स्थानीय निकायों से जोड़ें

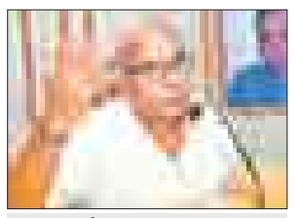

मदन मोहन झा स्मृति व्याख्यान में बोले प्रो जेबीजी तिलक

संवाददाता,पटना

स्थानीय निकायों की मजबूती से ही प्राथमिक शिक्षा सुधरेगी. सिर्फ सरकारी धन से इसमें सुधार मुश्किल है. शिक्षा में सुधार के लिए स्थानीय निकायों को स्कूल से जोड़ा जाना चाहिए. केंद्र व राज्य की सरकारें इस पर विशेष ध्यान दें. ये बातें राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) के वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो जेबीजी तिलक कहीं. वह शनिवार को डॉ मदन मोहन झा की छठी पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे. इसका विषय था 'प्राथमिक शिक्षा : एक मौलिक अधिकार'. उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद अधिकतर राज्यों में छह से 14 साल तक के बच्चों को यह अधिकार नहीं मिल पा रहा है.

आरटीइ का बढ़े दायरा

विधान पार्षद केदार नाथ पांडेय ने कहा कि आरटीइ के दायरे में शून्य से 18 वर्ष के बच्चों को लाया जाना चाहिए. डॉ झा जब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बने, तो पदाधिकारियों व शिक्षक संघों के बीच की दूरी खत्म हो गयी थी.

प्रशंसा करते नहीं थकते

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसएन झा ने कहा कि डॉ झा ने राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए सार्थक पहल किया था. यही कारण है कि शिक्षक से लेकर कुलपति तक डॉ झा की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं. मौके पर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के निदेशक डीएम दिवाकर, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निशा झा, शिक्षांश की अध्यक्ष निहारिका झा, प्रो विनय कंठ आदि मौजूद थे.

आज गांव में पढ़ता तो मजदूर ही बनता

पूर्व डीजीपी डीएन गौतम ने कहा कि आज गांवों के सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है. जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो गांव व शहर के स्कूलों में ज्यादा का फर्क नहीं था. गांव के पढ़े बच्चे भी उच्च शिक्षा हासिल करते थे और अच्छे स्कूल के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे. आज अगर मैं गांव में पढ़ा होता, तो मनरेगा मजदूर ही बन पाता. सरकारें सिर्फ सपना दिखा रही हैं. असमानता बढ़ी है.

डीएन गौतम

विश्वासघात का बदला नरेंद्र मोदी को वोट

सीवान के गांधी मैदान में सभा को संबोधित करते पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी.

- सीवान की जनाक्रोश सभा में बोले नंदकिशोर यादव
- केंद्र में कांग्रेस के रहते, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं : मोदी
- छोटे दलों को वोट देकर उसे बरबाद न करें : सीग्रीवाल

प्रभात खबर टोली, सीवान/पटना

पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि आज सब लोग यूपीए सरकार व महंगाई से मुक्ति चाहते हैं. देश के नौजवानों को पता चल चुका है कि कांग्रेस केंद्र में रहेगी, तो उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है. 27 अक्तूबर की रैली में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में आयेंगे. इतनी बड़ी रैली करनी है कि लालू, रामविलास पासवान व नीतीश कुमार को मालूम हो जाये कि बिहार की जनता उनके साथ नहीं, बल्कि मोदी व भाजपा के साथ है. वह शनिवार को यहां गांधी मैदान में जनाक्रोश सभा को संबोधित कर रहे थे.

विधानसभा में विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने जनता से अपील की कि लोकसभा चुनाव में अपना एक भी वोट बरबाद मत कीजिए और विश्वासघात का बदला नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में वोट देकर लिजिए.

दिल्ली का रास्ता बिहार से

सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कहा कि हम बता देंगे दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है और बिना बिहार के सहयोग से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है. जिसको प्रधानमंत्री बनना है, उसको बिहार का समर्थन चाहिए और बिहार का समर्थन नरेंद्र भाई मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है.

पूर्व श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को अपना वोट देकर उसे बरबाद न कीजिए. ये छोटे-छोटे दल केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करते हैं. सभा को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, राधा मोहन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, विधायक जनक सिंह, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, संजय चंद्रवंशी, कन्हैया राजवार ने भी संबोधित किया.

उपहास के पात्र बन रहे सुमो : शिवानंद

पटना. जदयू सांसद शिवानंद तिवारी ने भाजपा नेता सुशील मोदी को भांजू कहते हुए एक बार फिर निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि आजकल वे बयानों की चांदमारी की मुद्रा में हैं. वैसे तो रोज नया मसाला तैयार करना कोई साधारण काम नहीं है. लेकिन, लगता है उन्होंने काफी रियाज किया है. रोज-रोज बयान देने का एक खतरा भी है कि कभी-कभी बयान देनेवाले उपहास के पात्र बन जाते हैं. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को नहीं, मुख्यमंत्री को लाभ मिलेगा, इस बयान में मोदी का अद्भुत चिंतन दिखता है. विशेष दर्जा के प्रावधान में किसी व्यक्ति को लाभ देने का प्रावधान नहीं है, भले ही मुख्यमंत्री ही क्यों न हो. अपने बयान से मोदी ने खुद को उपहास का पात्र बना लिया है. बड़ा काम करनेवालों को सफलता खुद-ब-खुद मिलती है. भांजू नेता की बेचैनी से यह लगता है मानों बिहार को दर्जा मिलनेवाला है. अगर ऐसा है, तो उनके मुंह में रसमलाई.

लोजपा-भाजपा के कई नेता जदयू में

पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लोजपा व भाजपा के नेताओं का स्वागत करते जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह.

संवाददाता, पटना

भाजपा व लोजपा के कई नेताओं ने शनिवार को जदयू का दामन थाम लिया. प्रदेश कार्यालय में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में मनोरंजन गिरि, पूनम गिरि, राजू भारती, वीरेंद्र भारती, संतोष कुमार भारती, डॉ यशवंत गिरि व सुरेंद्र गिरि सहित गोस्वामी समाज के 345 नेताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की. इन नेताओं ने कहा कि बिहार में जदयू ही ऐसी पार्टी है, जो जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है. भाजपा-लोजपा केवल सत्ता पाने की नीति पर काम करती रही है. मिलन समारोह में सांसद डॉ रंजन प्रसाद यादव, रामधनी सिंह, राजेश्वर राज, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह, संतोष निराला, रुदल राय, संजय कुमार सिंह उर्फ गांधीजी, श्याम किशोर सिंह, रवींद्र सिंह, डॉ नवीन कुमार आर्य, छोटू सिंह, रणवीर नंदन, ललन कुमार सरफ, नंद किशोर कुशवाहा, ओमप्रकाश सिंह सेतु आदि मौजूद थे.

किसान नहीं, कॉरपोरेट घरानों के नेता हैं मोदी

संवाददाता, पटना

■ गुजरात भेजे गये किसानों का नाम हो सार्वजनिक : रणवीर नंदन

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी (नमो) व बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी (सुमो) को जदयू ने कॉरपोरेट घरानों का नेता बताया है. पार्टी प्रवक्ता प्रो रामकिशोर सिंह व महासचिव रणवीर नंदन ने कहा कि इन दोनों भाजपाइयों को किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है. न केवल नेता, बल्कि भाजपा के एजेंडे से ही गांव-गरीब, किसान, मजदूर, ठेले-खोमचे वाले गायब हैं. भाजपा कॉरपोरेट घरानों की कठपुतली बन चुकी है.

उन्होंने कहा कि गुजरात में नकली किसानों को भाजपा ने भेजा है. यदि यह सच नहीं, तो वे गुजरात जानेवाले किसानों का नाम सार्वजनिक करें. साथ ही यह भी बताये कि गुजरात भेजे गये किसानों ने कौन-सी फसल उपजाने में महारत हासिल की है. पशुपालकों को भेजा गया है, तो उनका नाम भी सार्वजनिक किया जाये. सुशील मोदी को कृषि के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है. वे गेहूं व जौ की बाली में फर्क नहीं समझते हैं. चना व मसूर का पौधा भी नहीं पहचानते हैं. अरबपतियों की चिंता करनेवाली भाजपा ने कभी किसानों के बारे में नहीं सोचा. वाणिज्य मंत्री के रूप में मोदी ने सिर्फ व्यापारियों की ही चिंता की.

गांव-गांव जायेंगे कार्यकर्ता

संवाददाता,पटना

प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांव-गांव जायेंगे और लोगों को खाद्य सुरक्षा व भूमि अधिग्रहण बिल के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी देंगे. युवा कांग्रेस के नेता आपके द्वार कार्यक्रम अभियान के तहत किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति के घर रात्रि विश्राम भी करेंगे. प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष कुमार आशीष ने बताया कि अभियान की शुरुआत देशरत्न डॉ राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल बांसघाट से 17 सितंबर को होगी. पहले चरण में पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भभुआ, औरंगाबाद, गया व जहानाबाद जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया जायेगा. इसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सातव, सांसद मीनाक्षी नटराजन, सांसद अशोक तंवर, बिहार कांग्रेस प्रभारी सीपी जोशी, प्रभारी सचिव केएल शर्मा व परेश धनानी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी सहित सभी वरीय नेता मौजूद रहेंगे.

मीडिया से बातचीत करते प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुमार आशीष.

■ 17 को राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल से होगी शुरुआत

समय पर पूरी होंगी रेल परियोजनाएं

जदयू अध्यक्ष के पत्र के जवाब में रेल मंत्री ने दिया भरोसा

मधेपुरा से पूर्णिया के बीच आमान परिवर्तन पर चल रहा काम

संवाददाता, पटना

रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा है कि मधेपुरा से जुड़ी रेल परियोजनाओं को ससमय पूरा करने के लिए प्रयास जारी है. जदयू अध्यक्ष शरद यादव के पत्र के जवाब में रेल मंत्री ने कहा है कि इलाके में रेल खंड बनाने का काम चल रहा है और चालू वित्तीय वर्ष में कई रेल खंडों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा. मंत्री ने बनमनखी से बिहारीगंज के बीच प्रस्तावित रेल खंड के निर्माण में राशि कम होने की बात स्वीकारी है.

पैसे की कमी बनी बाधा

उन्होंने कहा है कि लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रेलवे ने 1.78 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. बावजूद इसके राशि की कमी आ रही है. रेल प्रशासन की कोशिश होगी कि वह मधेपुरा या इससे जुड़े रेल खंडों का काम तत्परता से पूरा कर सके. मधेपुरा से पूर्णिया के बीच अमान परिवर्तन पर तेजी से काम हो रहा है. श्री यादव ने 143 किमी लंबे रेल खंड मानसी-सहरसा-दौरम मधेपुरा-पूर्णिया और 28 किमी लंबे बनमनखी-बिहारीगंज रेल खंड के अमान परिवर्तन का काम तेजी से पूरा करने के लिए और राशि जारी करने की मांग की थी.

419.20 करोड़ हुए खर्च

मंत्री ने कहा है कि मधेपुरा से पूर्णिया रेल खंड के अमान परिवर्तन पर 477.89 करोड़ रुपये खर्च किये जाने थे. इसमें से अब तक 419.20 करोड़ खर्च हो चुका है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए 18.75 करोड़ आवंटित किया गया है. 22 किमी लंबे सहरसा-दौरम मधेपुरा के बीच अमान परिवर्तन का काम 2010 में ही पूरा हो चुका है. दौरम मधेपुरा से पूर्णिया के बीच अमान परिवर्तन का काम अंतिम चरण में है. दो अन्य सेक्शन में 22 किमी लंबा दौरम मधेपुरा-मुरलीगंज और 18 किमी लंबे मुरलीगंज से बनमनखी के बीच का इंजीनियरिंग काम हो चुका है.

मुख्य संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद इसे चालू कर दिया जायेगा. बनमनखी से कृत्यानंद नगर के बीच 22 किमी लंबे रेल खंड को भी सीआरएस निरीक्षण के बाद चालू कर दिया जायेगा. जबकि, कृत्यानंदनगर से पूर्णिया के बीच 10 किमी लंबे रेल खंड पर भी तेजी से काम चल रहा है. इसे चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा. मंत्री ने कहा कि रेल प्रशासन की कोशिश है कि 40 किमी लंबे रेल खंड मधेपुरा से बनमनखी के बीच इसी वित्तीय वर्ष से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाये.

मुसहर विकास योजना | तीन साल बाद भी सात जिलों में नहीं शुरू हुआ काम

स्टोर रूम में ही खराब हो गयी स्ट्रीट लाइट

विवेक मिश्रा, पटना

मुसहर समुदाय के जीवन स्तर में सुधार के लिए शुरू की गयी एक सरकारी योजना बीच रास्ते में

फंसी रह गयी. 2009-10 में 'मुसहर विकास योजना' 13 जिलों के लिए शुरू की गयी थी. योजना का मकसद था मुसहर बहुल क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना. योजना को करीब तीन साल हो गये, लेकिन केवल पांच जिलों में ही सोलर स्ट्रीट लाइट लग पायी. बाकी सात जिलों में सामान पहुंचा, लेकिन स्टोर रूम में ही रखा रह गया. बिहार रेन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) को इस काम के लिए एक करोड़ 10 लाख रुपये मिले थे. महालेखाकार (एजी) द्वारा तैयार ब्रेडा की ऑडिट रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा हुआ है. यह ऑडिट रिपोर्ट 15 से 29 अप्रैल, 2013 के बीच करायी गयी थी.

13 जिलों को मिलना था लाभ

बेतिया, नालंदा, सुपौल, जमुई, नवादा, मधुबनी, समस्तीपुर, कैमूर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पटना, वैशाली और गया.

जो नहीं लग पायीं

योजना के तहत बेतिया में 17, जमुई में 14, नवादा में 13, मधुबनी में 46, समस्तीपुर में 15, मुजफ्फरपुर में 18, वैशाली में 11 व गया में 84 स्ट्रीट लाइट लगायी जानी थी.

344 में लगीं 127 स्ट्रीट लाइटें

कंपनी को 13 जिलों में कुल 344 सोलर स्ट्रीट लगानी थी. लेकिन नालंदा, सुपौल, कैमूर, भोजपुर, पटना में ही 127 सोलर स्ट्रीट लगायी गयी. जबकि 217 सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के ढाई साल बाद भी नहीं लगाये गये.

ब्रेडा का जवाब : ब्रेडा ने इस संबंध में एजी को बताया कि सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गयी थी. लेकिन कुछ जिलों में अधिष्ठापित नहीं हो पायी है.

विलंब दंड की वसूली नहीं

इस योजना (2009-10) के जरिये 32 हजार रुपये की दर से कुल 344 सोलर स्ट्रीट लाइट 13 जिलों के मुसहर बहुल क्षेत्रों में लगायी जानी थी. इसमें निविदा के तहत भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को सफल घोषित किया गया. 09 जून, 10 को कंपनी से एकरारनामा हुआ. अप्रैल, 2013 तक कंपनी को 35 लाख 74 हजार 497 रुपये दे दिये गये. लेकिन कंपनी निर्धारित समय में स्ट्रीट लाइट आपूर्ति में विफल रही. जबकि एकरारनामा में विलंब दंड भी संबंधित कंपनी को देना था. इस योजना में कुल 5 लाख रुपए विलंब दंड कंपनी पर है. लेकिन अब तक वसूली नहीं की गयी है. कई जिलों में समान स्टोर में ही खराब हो गये. पांच जिलों में लगाये गये अधिकांश स्ट्रीट लाइट भी खराब हो चुके हैं.

गया डीएम ने भी लिखा था खत

गया, जिलाधिकारी ने इस संबंध में 08-11-12 को ब्रेडा को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने लंबी अवधि से सोलर स्ट्रीट लाइट के स्टोर में पड़े रहने से बैटरी के डिस्चार्ज या डीप डिस्चार्ज होने की आशंका जतायी. जाहिर है कि बैटरी पर दो साल की वारंटी थी. दो साल से अधिक समय तक रखे रहने से बैटरी बेकार भी हो गई.

(रिपोर्ट 16वीं सीएसइ फैलोशिप के तहत प्रकाशित)